कर्नाटक राज्य और अन्य

बनाम

के.के. मोहनदास और आदि

1 अगस्त 2007

[पी.के. बालासुब्रमण्यन और ए.के. (माथुर, जे.जे.)

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963

126- खुली आंखों से और बिना किसी आपसी गलती के किए गए समझौते को सुधारने के लिए कोई भी पक्ष नहीं कह सकता- अधिक से अधिक यह तब हर्जाना मांग सकता है जब अवसर की चूक के कारण उसे कोई नुकसान होता है- जब कोई नुकसान नहीं दिखाया गया तो वादी नुकसान के लिए हर्जाना मांग भी नहीं सकता एवं न ही अपना दावा इस आधार पर पेश कर सकता कि सरकार ताड़ी की अवैध बिक्री को रोकने में विफल रही है- वादी, जो अनुभवी ठेकेदार हैं, को अवैध बिक्री के तथ्य के बारे में पता होना चाहिए और वे अज्ञानता का दावा नहीं कर सकते हैं- विधानसभा में सरकार के नीतिगत बयान के कारण सरकार के खिलाफ एस्टॉपेल का अनुरोध नहीं किया जा सकता है क्योंकि वादी उससे कभी भी गुमराज नहीं किया गया।

कर्नाटक राज्य अरक के व्यापार सहित राज्य के विभिन्न तालुकों में शराब बेचने के अधिकार की नीलामी कर रहा था। मुकदमे में वादी, स्वयं को उत्पाद शुल्क ठेकेदारों दिखाते हुए ने पहले और यहां तक कि उत्पाद शुल्क वर्ष 1989 के लिए भी संबंधित तालुकों से शराब बेचने के अधिकार की बोली लगाई थी। 90. 16.3.1990 को, वित्त मंत्री, कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में अपने बजट भाषण के दौरान 1.7.1990 से पूरे राज्य में ताड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की नीति अपनाने का बयान दिया।

28.5.1990 को, उत्पाद शुल्क वर्ष 1990-91 के लिए संबंधित तालुकों में अरक बेचने के अधिकार की नीलामी आयोजित की गई थी। वादी संबंधित नीलामियों में सबसे अधिक बोली लगाने वाले थे और अनुबंध उनके पक्ष में हुआ था। इस बीच, ताड़ी निकालने वालों ने प्रतिबंध के प्रयास का विरोध किया। यह प्रतिरोध वादी द्वारा अपनी उच्चतम बोली लगाने से पहले ही शुरू हो गया था।

आंदोलन को देखते हुए, सरकार ने प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया और दक्षिण कन्नड़ जिले के ताड़ी निकालने वालों द्वारा खींची गई ताड़ी को एक केंद्रीकृत सोसायटी के माध्यम से फेनी इकाइयों को बेचने की व्यवस्था करने और जैसा कि परिकल्पना की गई थी, वैसा एक केंद्रीकृत सोसायटी द्वारा खरीद को अंतिम रूप दिये जाने तक दक्षिण कन्नड़ की फेनी इकाइयों को आवंटित पेड़ों के टपरों से उत्पाद ताड़ी शुल्क आयुक्त

द्वारा निर्धारित कीमत पर खरीदने की अनुमति देने का आदेश जारी किया।

कुछ वादी पक्ष ने उच्च न्यायालय से गुहार लगाई कि राज्य सरकार को उत्पाद शुल्क वर्ष 1990-91 के दौरान दक्षिण कन्नड़ जिले के कुछ तालुकों में ताड़ी के दोहन या बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रभावी और उचित कदम उठाने का निर्देश देने के लिए एक परमादेश रिट जारी की जाए। राज्य को रिट याचिकाकर्ताओं के अनुबंध समाप्त करने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश मांगा गया और प्राप्त किया गया। रिट याचिकाकर्ताओं ने नीति वक्तव्य पर भरोसा किया और तर्क दिया कि उन्होंने उस आश्वासन के आधार पर उत्पाद शुल्क वर्ष 1990-91 के लिए अरक बेचने के अधिकार की बोली लगाई थी। उन्होंने राज्य को यह निर्देश देने की भी मांग की कि किस्ट राशि वर्ष 1990-91 के लिए किराये की बोली की दर पर एकत्र न की जाए, बल्कि इसे एक्सबे वर्ष 1989-90 के लिए बोली राशि की दरों पर ही एकत्र की जाए।

उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जहां यह नीति का मामला है वहां वचनबंधन रोक नहीं लगाई जा सकती है, और सरकार ने आपत्तियों का बयान दाखिल करके कहा है कि वह अवैध व्यापार को रोकने के लिए अपने साधनों के भीतर जो भी संभव है वह कर रही है।हालाँकि, राज्य द्वारा अनुबंध को समाप्त करने के प्रयास को 30.9.1990 तक रोक दिया गया था। यह मामला एसएलपी के माध्यम

से इस न्यायालय में लाया गया था। इस न्यायालय ने वादीगण को उचित सिविल न्यायालय में जाने का अधिकार देते हुए इसे खारिज कर दिया। इसके बाद वादी ने ये मुकदमे दायर किये। ट्रायल कोर्ट ने माना कि चूंकि राज्य जनता को ताड़ी के दोहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की नीति को सफलतापूर्वक लागू करने में विफल रहा है, इसलिए राज्य और ठेकेदार के बीच हुए अनुबंध के संदर्भ में राज्य को किस्ट राशि का दावा करने से रोक दिया गया था। अधीनस्थ अपीलीय अदालत भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ी और अपीलें खारिज कर दीं। उच्च न्यायालय ने वचन- बंधन की याचिका को बरकरार रखते हुए दूसरी अपील को खारिज कर दिया।

अपील न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया

1. विशिष्ट राहत अधिनियम की 26 के तहत, एक उपकरण या अनुबंध को सुधारा जा सकता है जब धोखाधड़ी या पार्टियों की आपसी गलती के माध्यम से, एक अनुबंध या लिखित रूप में अन्य उपकरण उनके वास्तविक इरादे को व्यक्त नहीं करता है। हालाँकि, यदि पार्टियों ने जानबूझकर लिखित दस्तावेज़ में कुछ छोड़ दिया है, तो उसे सुधार के उपाय का सहारा नहीं लिया जा सकता है। यहां, पार्टियों ने लिखित अनुबंध में प्रवेश किया है और माना जाता है कि ताड़ी के व्यापार पर प्रतिबंध को लागू करने के संबंध में कोई शर्त शामिल नहीं है।

दक्षिण कन्नड़ जिले में जनता। न ही अनुबंध की शर्तों को निर्धारित

करने के मामले में किसी आपसी गलती के मामले की पैरवी की गई है। अनुबंध में प्रवेश करने में राज्य की ओर से धोखाधड़ी की कोई दलील नहीं है। अनुबंध की शर्तों पर, वादी ने मासिक किश्तों में बोली राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व पर उत्पाद शुल्क वर्ष 1990-91 के लिए अरक बेचने का अधिकार प्राप्त किया था। वादी द्वारा सुधार की राहत के लिए आधार स्थापित करने के लिए रखी जा रही दलीलों में किसी आधार के अभाव में, केवल संशोधन के माध्यम से प्रार्थना जोड़ना उन्हें सुधार की राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।(पैरा91 1708, बी, सी, डी, ई हंट बनाम रुसमैनियर एडमिनिस्ट्रेटर 8 व्हीटन 174, का उल्लेख किया गया है।

2. वादी ने यह स्थापित नहीं किया था कि सरकारी आदेश में दर्शाए गए फीनी इकाइयों के विपरीत सार्वजनिक रूप से ताड़ी की अवैध दोहन और बिक्री को रोकने में राज्य सरकार की असमर्थता के कारण उन्हें कोई नुकसान हुआ था। यह दिखाने के लिए भी कोई सबूत पेश नहीं किया गया है कि ताड़ी की बिक्री का अरक की बिक्री से कोई सीधा संबंध है या अरक की बिक्री की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ता है। राज्य ने स्पष्ट रूप से दलील दी है कि ताड़ी के दोहन और बिक्री का अरक की बिक्री से कोई लेना- देना नहीं है और अरक पीने वाले आम तौर पर ताड़ी नहीं लेते हैं। ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर राज्य द्वारा अपनाए गए रुख को गलत

या अस्थिर पाया जा सके। इस प्रकार, तथ्यों पर, केवल वादी के किस्त का भुगतान करने के दायित्व के संबंध में उपकरण के सुधार के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। अधिक से अधिक, वादी को यह स्थापित करने पर राज्य के खिलाफ क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा करने का अधिकार हो सकता है कि जनता पर ताड़ी की बिक्री और निषेध की अपनी नीति लागू करने में सरकार की कथित विफलता के कारण उन्हें नुकसान हुआ है और इसकी मात्रा निर्धारित करके ऐसे नुकसान का. भले ही कोई नुकसान हुआ हो, यह वादी को उपकरण को ठीक करने का अधिकार नहीं देता है और वह भी इस आशय से कि किस्ट का भुगतान करने का उनका दायित्व पिछले उत्पाद शुल्क वर्ष 1989-90 के लिए उनकी बोलियों पर आधारित होना चाहिए। वादीगणों के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि राज्य सरकार ने कभी उनसे कहा हो कि जनता को ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने में विफल होने की स्थिति में, वादीगणों को केवल वर्ष 1989-90 की किस्त राशि का भुगतान करना होगा। वादी द्वारा बोलियों से पहले किसी भी बातचीत के दौरान ऐसा कोई समझौता या अनुबंध नहीं था। वास्तव में, यह खुली नीलामी का मामला था, जिसमें एक क़ानून के आलोक में शर्तें निर्धारित की गई थीं और वादी ने अपनी बोली लगाई थी। इसलिए शर्तों के संबंध में आपसी गलती या अनुबंधों के निष्पादन में धोखाधड़ी का कोई अवसर नहीं था। इस प्रकार, अनुबंधों के एक हिस्से को सुधारने के लिए अधीनस्थ अदालतों द्वारा की गई राहत का अनुदान पूरी तरह से अनुचित

है।और कानून में स्पष्ट रूप से अस्थिर है। डिक्री के उस हिस्से को अनिवार्य रूप से अलग रखा जाना चाहिए। (पैरा10,12 और 131 1708-जी:709-ई,एफ,जी;710-ए,बी,सी)

3. जो बचा है वह प्रॉमिसरी एस्टोपेल का मामला है। यहां इस वादे को संबंधित मंत्री का बजटीय भाषण बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने दक्षिण कन्नड़ जिले में जनता को ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। सबसे पहले, उच्च न्यायालय ने कुछ वादी पक्ष द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि इन मामलों में वचनबंधन का कोई सवाल ही नहीं उठता। उक्त निर्णय को चुनौती देने वाली अपील की विशेष अनुमति की याचिका को इस न्यायालय ने खारिज कर दिया और वादी पक्ष को सिविल न्यायालय में जाने की छूट दे दी। सिविल कोर्ट में जाने के लिए आरक्षित अधिकार वादी को कुछ वादी द्वारा दायर रिट याचिकाओं में पहले से ही अस्वीकार किए गए वचन विबंध की याचिका के साथ सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं देता है। न ही यह अदालत को उच्च न्यायालय द्वारा तय की गई बातों से पीछे हटने और वचन- बंधन के मामले को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। सिविल कोर्ट का रुख यह स्थापित करने के लिए हर्जाने के लिए मुकदमा करने के उद्देश्य से किया गया था कि विधानसभा में भाषण द्वारा उठाई गई उम्मीदों और एक नीति के रूप में परिकल्पित निषेध को लागू करने में राज्य की विफलता के कारण उन्हें नुकसान हुआ

था। [पैरा 14] [710- सी, डी, ई, एफआई एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्रा. लिमिटेड एवं अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1986] 1 एस.सी.सी. 133; भारत संघ और अन्य बनाम गणेश राइस मिल्स और अन्य, जेटी (1998) 9 एससी 51 और एम/ जेड पाइन केमिकल्स लिमिटेड और अन्य। वी. मूल्यांकन प्राधिकारी और अन्य। [1992] 2 एस.सी.सी. 683, संदर्भित.

4. वादी का मामला यह नहीं है कि जनता को ताड़ी की बिक्री की अनुमति दी गई थी। उनका मामला यह है कि सहकारी समितियों के माध्यम से ताड़ी की खरीद और फेनी इकाइयों को आपूर्ति करने का प्रस्ताव करते हुए एक बाद की अधिसूचना जारी की गई थी। ऐसा नहीं लगता कि सरकार अपने नीतिगत उद्देश्य से भी पीछे हट गयी हो। लेकिन वादी के मामले से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ताड़ी निकालने वालों द्वारा ताड़ी की बिक्री जनता को रोकने के लिए बनाई गई नीति को पूरी तरह से लागू नहीं कर सकी। इससे, अधिक से अधिक, वादी पक्ष को यह स्थापित करने पर राज्य से क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार मिल जाएगा कि सरकार की ऐसी विफलता के कारण उन्हें क्षति हुई है। [पैरा 17] 1711-सी,डी, ईजे

5. वादी सभी अनुभवी उत्पाद शुल्क ठेकेदार हैं जो खुली नीलामी में शराब बेचने के अधिकार के लिए बोली लगा रहे हैं। यह कुख्यात है कि ये नीलामियाँ अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हैं और मौजूदा ठेकेदार द्वारा अपने गढ़ को

संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। यह भी कुख्यात है कि इनमें कितनी कीमतें मिलती थीं

प्रतिस्पर्धा के कारण नीलामी में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिखती है। राज्य ने बताया है कि विभिन्न अन्य केंद्रों के आंकड़ों में वृद्धि वर्ष 1989-90 की राशि से 300% अधिक हो गई है। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वादी द्वारा बोली उनकी गणनाओं पर आधारित नहीं थी और अपने संबंधित क्षेत्रों में अरक बेचने के अपने अधिकार को संरक्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा को दूर करने की दृष्टि से नहीं थी। पैरा 18] [711- ई, एफ जी

6. वादी ने जो जोखिम उठाया था वह एक व्यावसायिक उद्यम था। यदि उन्हें लगा कि जोखिम नहीं उठाया जा सकता है, तो यह उनका काम था कि वे अनुबंध को पूरी तरह से अस्वीकार कर दें। वास्तव में, जब जुलाई और अगस्त 1990 के महीनों के लिए सहमति के अनुसार वादी द्वारा किस्त राशि भेजने में विफलता के कारण सरकार ने स्पष्ट रूप से अनुबंध समाप्त करने की कोशिश की, तो वादी ने इस तरह की समाप्ति पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त किए और चले गए समझौतों के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए वेंडिंग रैक के साथ आगे बढ़ें। अनुबंध के निष्पादन पर जोर देने और इसके तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के बाद, वादी अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को अस्वीकार करने के हकदार नहीं हैं। पारंपरिक या वचन संबंधी

रोक का कोई भी मामला यहां उत्पन्न नहीं होगा। रोक पर निष्कर्ष संबंधित मंत्री द्वारा विधानसभा में अपने भाषण में किए गए वादे या प्रस्ताव और सार्वजनिक रूप से ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध की नीति को लागू करने में सरकार की गिरावट पर आधारित है। वादी द्वारा उठाई गई याचिका उनकी बोलियों के आधार पर और सरकार के साथ उनके द्वारा किए गए लिखित अनुबंधों में निहित दायित्व से मुक्त होने को उचित ठहराने वाली एस्टॉपेल की याचिका को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं रखती है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि अनुबंध में कोई ऐसी शर्त शामिल है जो गलती है या इसमें कोई शर्त शामिल है जो राज्य पर कोई दायित्व डालती है जिसे राज्य पूरा करने में विफल रहा है।

[पैरा 19 और 20] [711- जी, एच; 712- ए, बी, सी, डी)2002.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7102-7105/2002

बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के 1998 की आर.एस.ए. संख्या 892-895 मे पारित निर्णय और आदेश 23.02.2001 से

संजय आर.हेगड़े, अनिल के.मिश्रा, विक्रांत यादव एवं शशिधर अपीलकर्ता की ओर से।

एस.एन. भट, डी.पी. चतुर्वेदी, एन.पी.एस. पंवार, कृष्णेदु दत्त, रोहित प्रिया रंजन, डी.एस.के. वर्मा तथा तान्या शर्मा विपक्षीगण की ओर से।

न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया

सभी अपीलों में, प्रतिवादी, कर्नाटक राज्य और उपायुक्त (उत्पाद शुल्क) अपीलकर्ता हैं। चार अपीलें ओ.एस. वाले चार मुकदमों से उत्पन्न होती हैं। प्रथम अतिरिक्त मुंसिफ, मैंगलोर की अदालत की फाइल पर 1990 की संख्या 1261, 1262, 1263 और 1264। मुकदमों का फैसला वादी पक्ष के पक्ष में सुनाया गया था, जो उत्पाद शुल्क वर्ष 1990-91 के लिए 1.7.1990 से 30.6.1991 की अवधि को कवर करने वाले उत्पाद शुल्क ठेकेदार और कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले के विभिन्न तालकों में अरक बेचने के अधिकार के बोली लगाने वाले थे। . डिक्री से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन, मैंगलोर की अदालत में चार अपीलें दायर कीं। ट्रायल कोर्ट के आदेशों की पुष्टि करते हुए अपीलें खारिज कर दी गईं। कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई चार दूसरी अपीलों का भी यही हश्र हुआ। विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें इस प्रकार चार मुकदमों में दी गई डिक्री को चुनौती देती हैं।

2. कर्नाटक राज्य हर साल राज्य के विभिन्न तालुकों में शराब बेचने के अधिकार की नीलामी करता है। इनमें अरक का व्यापार भी शामिल है। मुकदमे में वादी, उत्पाद शुल्क ठेकेदारों ने स्वयं दिखाते हुए, पहले और यहां तक कि उत्पाद शुल्क वर्ष 1989-90 के लिए संबंधित तालुकों से

शराब बेचने के अधिकार की बोली लगाई थी। 16.3.1990 को, कर्नाटक सरकार के वित्त मंत्री ने विधानसभा में अपने बजट भाषण के दौरान निम्नलिखित बयान दिया।

> "राज्य चरणबद्ध तरीके से ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की नीति का पालन कर रहा है। वर्तमान में, सात जिलों में ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैं 1.7.1990 से प्रतिबंध को पूरे राज्य में बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। राजस्व में अनुमानित हानि 60 करोड़ रुपये है। आशा है कि इस हानि का एक हिस्सा उच्च अरक किराये और नियमों और विनियमों के बेहतर कार्यान्वयन से पूरा हो जाएगा।"

संयुक्त रूप से आजमाए गए सूट में बजट भाषण को प्रदर्श पी-1 के रूप में चिह्नित किया गया था। वादी पक्ष के अनुसार, इस प्रकार घोषित नीति को लागू करने के लिए सरकार द्वारा 2.5.1990 को कैबिनेट की बैठक में एक निर्णय भी लिया गया था। लेकिन, ताड़ी की अवैध दोहन और बिक्री पर रोक नहीं लगायी गयी. 21.5.1990 को, कुंदापुर, उडुपी, बंटावल, सुलिया, पुत्तूर और बेलथांगडी तालुकों में अरक बेचने का अधिकार उत्पाद शुल्क वर्ष 1990-91 के लिए रखा गया था। वादी संबंधित नीलामियों में सबसे अधिक बोली लगाने वाले थे और संबंधित बोलियाँ उनके पक्ष में गिर

गईं। 29.6.1990 को वादी द्वारा प्रतिवादियों के साथ औपचारिक अनुबंध किया गया। औपचारिक अनुबंधों को सूट में रक्षा प्रदर्शनी डी-6 आदि के रूप में चिह्नित किया गया था। इस बीच, चारा काटने वालों ने कुड़का उठाया और यहां तक कि प्रतिबंध के प्रयास को भी खारिज कर दिया। इसका विरोध भी शुरू हो गया था वादी द्वारा अपनी उच्चतम बोली लगाने से पहले।

3. आंदोलन को देखते हुए सरकार ने प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया और 29.6.1990 को एक आदेश जारी किया। जबकि जनता के लिए ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रखा गया था, दक्षिण कन्नड़ जिले के ताड़ी निकालने वालों द्वारा खींची गई ताड़ी की बिक्री की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया, एक केंद्रीकृत सोसायटी के माध्यम से फेनी इकाइयों को और बी दक्षिण कन्नड़ की फेनी इकाइयों को अनुमति दी गई। आवंटित पेड़ों के ताड़ी फ्रम टैपर को एक केंद्रीकृत सोसायटी द्वारा खरीद को अंतिम रूप देने तक उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा तय की जाने वाली कीमत पर खरीदें, जैसा कि परिकल्पना की गई है।

4. वादी का मामला है कि ताड़ी निकालने वालों द्वारा जिले में खुलेआम ताड़ी बेचकर उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किया गया। राज्य ने इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठाए। इसलिए, कुछ वादी ने रिट याचिकाओं के साथ कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, रिट

याचिका संख्या 16317 से 16319 1990 तक। डब्लूआरए याचिकाओं में मुख्य प्रार्थना राज्य सरकार को प्रभावी और उचित कदम उठाने का निर्देश देने के लिए एक परमादेश रिट जारी करना था। एस्के वर्ष 1990-91 के दौरान दक्षिण कन्नड़ जिले के उडुपी, कुंदापु र और डी बेलथांगडी तालुकों में ताड़ी के दोहन या बिक्री पर रोक लगाने के लिए। राज्य को रिट याचिकाकर्ताओं के अनुबंध को समाप्त करने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश मांगा गया था और प्राप्त किया गया था। रिट याचिकाकर्ताओं ने ऊपर उद्धृत नीति कथन पर भरोसा किया और तर्क दिया कि उन्होंने उस आश्वासन के आधार पर उत्पाद शुल्क वर्ष 1990-91 के लिए अरक बेचने के अधिकार की बोली लगाई थी और उस नीति को लागू करना सरकार का कर्तव्य था। उन्होंने राज्य को वर्ष 1990-91 के लिए किराये की बोली की दर पर किस्ट राशि एकत्र न करने का निर्देश देने की भी मांग की, बल्कि इसे केवल उत्पाद शुल्क वर्ष 1989-90 के लिए बोली राशि की दरों पर एकत्र करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। वादी पक्ष द्वारा खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की गई थी। रिट याचिकाओं में प्रार्थनाओं के समर्थन में सरकार के विरुद्ध वचनबंधन का मामला भी रखा गया था। डिवीजन बेंच ने पाया कि जिस बारे में शिकायत की गई थी वह किसी भी व्यवसाय के लिए खतरे से ज्यादा कुछ नहीं था। प्रॉमिसरी एस्टोपेल की याचिका पर डिवीजन बेंच ने कहा: एफ

"प्रॉमिसरी एस्टोपेल उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि जहां यह नीति का मामला है, और कर्नाटक सरकार ने आपत्तियों का बयान दर्ज करके कहा है कि वह अवैध व्यापार को रोकने के लिए अपने साधनों के भीतर जो भी संभव है वह कर रही है।"

वादी की प्रार्थना पर, राज्य द्वारा अनुबंध को समाप्त करने के प्रयास को अदालत द्वारा राज्य को निर्देशित करते हुए एक विशिष्ट अवधि के लिए रोक दिया गया था।एच 30.9.1990 तक अनुबंध की प्रस्तावित समाप्ति को प्रभावी न करना। अपील की विशेष अनुमति के लिए याचिकाओं के माध्यम से मामला इस न्यायालय में लाया गया था।

इस न्यायालय ने प्रदर्शन पी- 29 आदेश द्वारा याचिकाओं को इस प्रकार खारिज कर दिया:

"याचिकाकर्ता के उचित से संपर्क करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राहत के लिए सिविल कोर्ट और अंतरिम रोक के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा 15.10.1990 तक कार्यवाही पर रोक लगाने की ये याचिकाएँ हैं बर्खास्त कर दिया गया।"

इसके बाद ये मुकदमे ट्रायल कोर्ट में दायर किए गए हैं। चूंकि विभिन्न वादपत्रों में कथन कमोबेश एक जैसे हैं और तथ्यात्मक स्थिति भी एक जैसी है, इसलिए यह पर्याप्त है कि वादों में से किसी एक का उल्लेख किया जाए।

5. वादपत्रों में, उत्पाद शुल्क वर्ष 1990-91 के लिए नीलामी के संबंध में संबंधित वादी के सफल बोलीदाता होने का पक्ष निर्धारित करने के बाद और पहले से ही विज्ञापित बजट भाषण का उद्धरण निर्धारित करने और बार- बार के बावजूद भी दलील देने के बाद अभ्यावेदन में, प्रतिवादी ताड़ी की अवैध टैपिंग और बिक्री को रोकने के लिए कार्रवाई करने में विफल रहे थे और संबंधित जिले में ताड़ी की टैपिंग और इसकी बिक्री को अधिकृत करने वाले सरकार के दिनांक 29.6.1990 के आदेश का उल्लेख करने के बाद, यह अनुरोध किया गया था कि राज्य ने पहले किए गए वादे का उल्लंघन किया और परिणामस्वरूप, राज्य को उच्च किस्त राशि एकत्र करने से रोक दिया गया। यह स्वीकार करने के बाद कि पिछले वर्ष 1989-90 की बोली के अनुसार जुलाई 1990 महीने की किस्ट राशि का भुगतान किया गया था और यह दलील देने के बाद कि अगस्त 1990 महीने की

किस्ट राशि का भुगतान भी उसी आधार पर किया गया है, यह था आगे दलील दी गई कि वादी भविष्य की किस्ट राशि भी उसी दर पर चुकाने को तैयार है क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। हम ओएस में शिकायत के पैराग्राफ 10 को निर्धारित करना उचित समझते हैं। 1990 का क्रमांक 1261:

"जब उत्पाद शुल्क आयुक्त ने जुलाई 1990 के महीने के लिए वादी से किस्त राशि की मांग की, तो वादी ने जुलाई 1990 के लिए उस दर पर किस्त माफ कर दी, जिसके लिए उसने उक्त तालुकों में पिछले वर्ष के दौरान बोली लगाई थी, अर्थात 31.00 लाख रुपये। करकला तालुक के लिए और बंतवाल तालुक के लिए 35,00 लाख रुपये पर। यह वादी द्वारा आगे बढ़ाए गए विवादों में उसकी प्रामाणिकता को दर्शाता है। वादी ने अगस्त 1990 के लिए किस्त राशि भी माफ कर दी है। वादी भविष्य में भी भुगतान करने को तैयार है किस्त राशि उसी दर पर, क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। वादी का वैध रूप से देय राशि से वंचित करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वादी को अधिक राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए वादी ने बोली

की पेशकश की थी। पूरी तरह से ताड़ी पर प्रतिबंध लगाने की सरकार की घोषणा पर. ऊपर बताई गई ए परिस्थितियों के तहत और चूँकि उक्त परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल दी गई हैं, प्रतिवादियों द्वारा वादी से उक्त राशि का दावा करना अनुचित है जो कि डिफ़ॉल्ट पक्ष हैं।"

इसके बाद यह दलील दी गई कि घटनाक्रम को देखते हुए प्रदर्शन पर जोर नहीं दिया जा सकता। वादी के पैराग्राफ 11 में यही कहा गया है

"मामले के किसी भी दृष्टिकोण में और मौलिक उल्लंघन के उपरोक्त पहलुओं के बावजूद, वादी का कहना है कि शराब बेचने की बाध्यता का उद्देश्य ताड़ी के अवैध दोहन और बिक्री के परिणामस्वरूप अपेक्षित सीमा तक असंभव हो गया है, जिसे वादी कर सकता था। नहीं रोका और जिसे प्रतिवादियों ने नहीं रोका, हालांकि वे ऐसा करने के लिए बाध्य थे। इसलिए, शराब बेचने और उच्च किस्त राशि का भुगतान करने के अनुबंध के निष्पादन की पर्यवेक्षण असंभवता है, जिसकी प्राप्ति वादे के उल्लंघन के कारण असंभव हो गई है प्रतिवादियों द्वारा और साथ ही कानून और व्यवस्था बनाए रखने में उनकी विफलता और

लापरवाही के कारण। इसलिए, डी वादी को उन तालुकों में शराब की बिक्री के अनुबंध के अनुसार प्रदर्शन करने के दायित्व से मुक्त किया जाता है, जिसके लिए वादी सफल बोलीदाता है। वादी है निषेधाज्ञा का दावा करने का हकदार है क्योंकि वादी के पास कोई अन्य उपाय नहीं है। इसमें शामिल तात्कालिकता को देखते हुए इस मुकदमे को पिछले धारा 80 नोटिस के बिना पुनर्जीवित किया जा सकता है।

6. जैसा कि हम वादपत्र को समझते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में सरकार की विफलता और वादी द्वारा किस्त के भुगतान के मामले में अनुबंध का पालन करना असंभव हो गया है। रोक की दलील पहले ही उद्धृत किए गए मंत्री के बजटीय भाषण पर आधारित है। इसका हवाला देकर इसकी पैरवी की जाती है

"इस प्रकार सरकार ने जनता से एक वादा किया कि ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा जिससे शराब की अधिक बिक्री हो सकेगी। वादी ने, उक्त वादे से अवगत होने के बाद, इसे प्रतिवादियों का एक मौलिक दायित्व और एक आवश्यक शर्त के रूप में माना। दक्षिण कन्नड़ जिले में शराब बेचने के अधिकार की नीलामी करते समय प्रस्ताव

की। 28.5.1990 को, जब मैंगलोर में उत्पाद शुल्क की नीलामी हुई, तो वादी के दिमाग में प्रतिवादी का उपरोक्त मौलिक प्रतिनिधित्व सबसे पहले चल रहा था।

इसके बाद एक दलील दी गई कि यह इस पर आधारित था कि संबंधित वादी- बोलीदाता द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक राशि की पेशकश की गई थी। प्रतिवादियों ने विभिन्न आपत्तियाँ उठाते हुए एक लिखित बयान दायर किया। सूट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए। यह बताया गया कि निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रयास कुछ ऐसा प्राप्त करने का प्रयास था जिसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था। यह दलील दी गई थी कि वादी की बोली स्वीकार किए जाने पर, "गुनिगे पात्रा' नाम से एक औपचारिक अनुबंध किया गया था और वादी इस प्रकार किए गए अनुबंध को निष्पादित करने के लिए बाध्य था और वादी अनुबंध की शर्तों से बंधा हुआ था। लिखित अनुबंध में ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने या इस तरह के प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य पर कोई दायित्व डालने के संबंध में कोई शर्त नहीं थी। इस दलील को भी खारिज कर दिया गया कि ताड़ी के दोहन और बिक्री पर प्रतिबंध से अरक में बिक्री बढ़ जाएगी। इस बात से इनकार किया गया कि सरकार ने जनता से

कोई वादा किया था कि ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस बात से इनकार किया गया कि वादी ने उस वादे के आधार पर उत्पाद शुल्क वर्ष 1990-91 के लिए अरक बेचने के अधिकार को छुपाया था। यह था इस बात से भी इनकार किया कि वादी की ओर से ताड़ी बेचने की पेशकश पूरी तरह से इस आश्वासन पर थी कि ताड़ी निकालने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जिन तथ्यों ने सरकार को ताड़ी की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाने और नई व्यवस्था करने के लिए मजबूर किया, वे सभी थे प्रस्थान करना। वादीगण ताड़ी निकालने वालों द्वारा प्रतिबंध का उल्लंघन करने के प्रयासों के तथ्य से अवगत थे और उन्होंने इसके बाद आँखें खोलकर अनुबंध में प्रवेश किया था। वादी पक्ष की बोली के समय भी ताड़ी निकालने वालों का आंदोलन जारी था। वादी अनुबंध की शर्तों और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य थे। आगे यह भी कहा गया कि, वास्तव में, जनता को बिक्री के लिए ताड़ी की ई अपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अवैध टैपिंग चल रही थी और उत्पाद शुल्क विभाग अवैध टैपिंग को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वादी उस राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य थे जो सरकार से उन्हें प्राप्त शराब बेचने के अधिकार के लिए प्रतिफल थी, जिसके पास शराब बेचने का विशेष विशेषाधिकार था। रिट याचिका को खारिज करने,

उसकी अपील और अपील के लिए विशेष अनुमति की याचिकाओं की पैरवी की गई। यह दलील दी गई कि अरक की बिक्री ताड़ी के दोहन या ताड़ी की बिक्री पर निर्भर नहीं थी। यह दलील दी गई कि सरकार को ताड़ी की दोहन पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में अपनी नीति बदलने का अधिकार है और ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध अरक की बिक्री के लिए एक शर्त नहीं थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि वादी सहमत किस्त के भुगतान से बच नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने राज्य के साथ औपचारिक अनुबंध में प्रवेश किया था, संबंधित उत्पाद शुल्क वर्ष के लिए उन्हें दिए गए अधिकार के संदर्भ में अरक की बिक्री की थी और वे नहीं थे किसी भी राहत का हकदार. यह भी दलील दी गई कि उत्पाद शुल्क वर्ष 1990-91 के लिए बोली राशि में वृद्धि सामान्य थी और अन्य स्थानों में वृद्धि का प्रतिशत, 13 संख्या है, उन कुछ केंद्रों में निर्धारित किया गया था, वृद्धि 100 प्रतिशत से ऊपर थी मैं वो पिछले साल का. मुकदमे खारिज किये जाने योग्य थे। (पैराडीएफ) फिर इस घोषणा से राहत की मांग करते हुए संशोधन किया गया कि वादी और राज्य के बीच मौजूद उत्पाद शुल्क अनुबंध को इस प्रभाव से सुधार कर लागू किया जा सकता है कि देय मासिक किस्त उत्पाद शुल्क वर्ष 1989-90 के दौरान प्रचलित दर पर होगी। समर्थन में कोई और दलील नहीं जोड़ी गई। एक अतिरिक्त लिखित बयान दायर

किया गया था कि लिखित अनुबंध ने पार्टियों का निष्कर्ष निकाला और मांग की गई घोषणा के अनुसार अनुबंध की शर्तों के तहत वादी के दायित्व को संशोधित किया गया, जबकि इसके द्वारा प्रदत्त अधिकार को बरकरार रखा गया, इसकी अनुमति नहीं थी।

7. मुकदमे में विभिन्न मुद्दे उठाए गए। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अंततः माना कि प्रतिवादियों को प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के सिद्धांत द्वारा वादी की बोली के अनुसार किस्ट राशि का दावा करने से रोक दिया गया था। यह इस आधार पर था कि मंत्री द्वारा दिया गया बजट भाषण इच्छुक बोलीदाताओं के लिए एक वादे के समान था, कि बोलीदाताओं ने उस वादे पर काम किया था और अधिक मात्रा की पेशकश की थी। चूंकि राज्य जनता को ताड़ी बेचने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने की नीति को सफलतापूर्वक लागू करने में विफल रहा था, इसलिए राज्य और ठेकेदार के बीच हुए अनुबंध के संदर्भ में राज्य को किस्ट राशि का दावा करने से रोक दिया गया था। अदालत ने खुद से यह नहीं पूछा कि क्या राज्य द्वारा ताड़ी के व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाने के कारण वादी को कोई नुकसान हुआ है। अदालत ने खुद से यह सवाल भी नहीं पूछा कि क्या वादी के दायित्व वाले अनुबंध के एक हिस्से को वादी में किए गए दावे के अनुसार सुधारा जा सकता है, या क्या वादी समग्र रूप से अनुबंध को अस्वीकार करने की स्थिति में थे

और क्या इस प्रकृति का सूट रखरखाव योग्य होगा। प्रतिवादियों की अपील पर, निचली अपीलीय अदालत ने उसी तर्ज पर कार्यवाही की और अपीलों को खारिज कर दिया। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि निचली अपीलीय अदालत की संपत्ति ने दलीलों और तरीके को नियंत्रित करने वाले कानून के सिद्धांतों पर अपना दिमाग लगाया। प्रतिवादियों द्वारा दायर की गई दूसरी अपील पर, उच्च न्यायालय को, हमें सम्मान के साथ कहना चाहिए, निर्णय के लिए उठे प्रश्नों पर अपना दिमाग ठीक से नहीं लगाया और दूसरी अपील को खारिज कर दिया, जिसे उसने प्रॉमिसरी एस्टोपेल की याचिका कहा था। इस प्रकार चार मुकदमों में दिए गए निर्णयों को इन अपीलों में चुनौती दी गई है।

1. निम्नलिखित डिक्री प्रदान की गई है।

> "इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि वादी के बीच मौजूद उत्पाद शुल्क अनुबंध और प्रथम प्रतिवादी इस आशय के सुधार द्वारा प्रवर्तनीय है देय मासिक किस्त उत्पाद शुल्क वर्ष के दौरान प्रचलित दर पर होगी 1989-90 इसके अलावा प्रतिवादियों को प्रभाव देने या लागू करने से रोका जाता है उत्पाद शुल्क वर्ष 1990-91 के लिए दक्षिण कन्नड़ जिले के करकला, बंटवाल, पुत्तूर, सुलिया, कुंडापुरा, उडुपी

और बेखांगडी तालुकों में शराब की खुदरा बिक्री के संबंध में वादी और प्रतिवादी के बीच हुए अनुबंध की शर्तें उसके तहत देय किस्त राशि या वैकल्पिक रूप से, प्रतिवादियों को स्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से उक्त तालुकों में 1989-90 के लिए निर्धारित दरों से अधिक दरों पर किस्त का दावा करने से रोका जाता है।"

9. विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 26 के तहत, एक उपकरण या अनुबंध को सुधारा जा सकता है जब धोखाधड़ी या पार्टियों की आपसी गलती के माध्यम से, एक अनुबंध या लिखित रूप में अन्य उपकरण उनके वास्तविक इरादे को व्यक्त नहीं करता है। "विशिष्ट राहत के कानून" पर अपने टैगोर लॉ लेक्चर में डॉ. बनर्जी के अनुसार, "यदि पार्टियों ने जानबूझकर लिखित दस्तावेज में से कुछ छोड़ दिया है, तो उसे शामिल नहीं किया जा सकता है।" सुधार के उपाय का सहारा लेकर. यहां, पार्टियों ने लिखित अनुबंध में प्रवेश किया है और माना जाता है कि दक्षिण कन्नड़ जिले में जनता के लिए ताड़ी के व्यापार पर प्रतिबंध को लागू करने के संबंध में कोई शर्त शामिल नहीं है। न ही वाद- विवाद में अनुबंध की शर्तों को निर्धारित करने के मामले में किसी आपसी गलती का मामला दर्ज किया गया है। अनुबंध में प्रवेश करने में राज्य की

ओर से धोखाधड़ी की कोई दलील नहीं है। अनुबंध की शर्तों पर, वादी ने मासिक किश्तों में बोली राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व पर उत्पाद शुल्क वर्ष 1990-91 के लिए अरक बेचने का अधिकार प्राप्त किया था। सुधार की राहत देने के लिए आधार स्थापित करने के लिए वादी द्वारा की जा रही दलीलों में किसी आधार के अभाव में, केवल संशोधन के माध्यम से प्रार्थना जोड़ना उन्हें सुधार की राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

10. इस मामले में जो सबसे अच्छा तर्क दिया गया है वह यह है कि अपने बजट भाषण में संबंधित मंत्री ने बड़े पैमाने पर जनता के सामने यह बात रखी थी कि वह पूरे राज्य में ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव कर रहे थे और इसने वादी को विश्वास करने के लिए प्रेरित किया था। कि अरक की बिक्री बढ़ जाएगी जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उत्पाद शुल्क वर्ष 1990-91 के लिए अरक बेचने के अधिकार के लिए ऊंची बोली लगाने की पेशकश की जाएगी। तथ्यों पर, राज्य के लिखित बयान से पता चलता है कि कई केंद्रों में, कीमतें बढ़ गई हैं काफी मात्रा में वृद्धि हुई और अन्य स्थानों में हुई वृद्धि की तुलना में, प्रासंगिक तालक में वृद्धि केवल मामूली थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि वादी ने यह स्थापित नहीं किया था कि उन्हें राज्य सरकार की असमर्थता के मद्देनजर कोई नुकसान हुआ था, जिसे वादी ने

सार्वजनिक रूप से फेनी इकाइयों के विपरीत अवैध दोहन और ताड़ी की बिक्री कहा था, जैसा कि संकेत दिया गया है। सरकारी आदेश. पी.डब्लू. वादीगण की ओर से परीक्षित 1 किसी के सन्दर्भ में नहीं दिखा सका

ऐसे किसी भी नुकसान का लेखा- जोखा। हम यहां वादी द्वारा रोक की अपनी याचिका के संबंध में नुकसान दर्शाए जाने के सवाल पर विचार नहीं कर रहे हैं, जिस पर अलग से विचार किया जाएगा। यहां जो बताने का इरादा है वह यह है कि वादी ने यह नहीं दिखाया है कि उनसे किए गए वादे के आधार पर अनुबंध में प्रवेश करने से उन्हें कोई नुकसान हुआ है, हालांकि लिखित दस्तावेज में यह प्रतिबिंबित नहीं है।

11. द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इन हैंड बनाम रूमानियर एडमिनिस्ट्रेटर, 18 व्हीटन 174) ने मुख्य न्यायाधीश मार्शल के माध्यम से बोलते हुए कानून में स्थिति का संकेत इस प्रकार दिया:

> "यह एक सामान्य नियम है, कि लिखित रूप में एक समझौता, या एक समझौते को निष्पादन में ले जाने वाला एक उपकरण, लिखित दस्तावेज से पहले की बातचीत या परिस्थितियों को बताते हुए पैरोल गवाही से अलग नहीं किया जाएगा।इस नियम को इक्विटी की अदालतों के साथ-

साथ कानून की अदालतों में भी मान्यता प्राप्त है, लेकिन इक्विटी की अदालतें धोखाधड़ी और गलती के मामलों में राहत देती हैं, जिन्हें कानून की अदालतों में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, इक्विटी की अदालत पार्टियों के इरादे को क्रियान्वित कर सकती है, जहां लिखित समझौता उस इरादे को व्यक्त करने में विफल रहता है

12. जैसा कि हमने देखा है, वादी के मामले का योग और उप-योग यह है कि उन्होंने इस विश्वास पर लिखित अनुबंध में प्रवेश किया कि जनता को ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की नीति लागू की जाएगी और इस उम्मीद के तहत अरक की बिक्री से उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। हम देख सकते हैं कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है कि ताड़ी की बिक्री का अरक की बिक्री से कोई सीधा संबंध है या अरक की बिक्री की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ता है। राज्य ने स्पष्ट रूप से दलील दी है कि ताड़ी के दोहन और बिक्री का अरक की बिक्री से कोई लेना- देना नहीं है और अरक पीने वाले आम तौर पर ताड़ी नहीं लेते हैं। ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर राज्य द्वारा अपनाए गए रुख को गलत या अस्थिर पाया जा सके। किसी भी घटना में, यह सुझाव देने के अलावा कि ऐसा होगा, वादी ने इस दलील को स्थापित

करने के लिए कोई कानूनी या स्वीकार्य सबूत पेश नहीं किया है

13. इस प्रकार, तथ्यों पर, हम पाते हैं कि केवल वादी के किस्त का भुगतान करने के दायित्व के संबंध में उपकरण के सुधार के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। अधिक से अधिक, वादी को यह स्थापित करने पर कि सरकार की निषेध और बिक्री की नीति लागू करने में कथित विफलता के कारण नुकसान हुआ है, राज्य के खिलाफ क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा करने का अधिकार हो सकता है।

जनता को ताड़ी की आपूर्ति और इस तरह के नुकसान की मात्रा स्थापित करके। भले ही कोई नुकसान हुआ हो, यह वादी को उपकरण को ठीक करने का अधिकार नहीं देता है और वह भी इस आशय से कि किस्ट का भुगतान करने का उनका दायित्व पिछले उत्पाद शुल्क वर्ष 1989-90 के लिए उनकी बोलियों पर आधारित होना चाहिए। वादीगणों के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि राज्य सरकार ने कभी उनसे कहा हो कि जनता को ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने में विफल होने की स्थिति में, वादीगणों को केवल वर्ष 1989-90 की किस्त राशि का भुगतान करना होगा। वादी द्वारा बोलियों से पहले किसी भी बातचीत के दौरान ऐसा कोई समझौता या अनुबंध नहीं था। वास्तव में, यह एक क़ानून के

आलोक में निर्धारित शर्तों पर खुली नीलामी का मामला था और वादी ने अपनी बोली लगाई। इसलिए शर्तों के संबंध में आपसी गलती या अनुबंधों के निष्पादन में धोखाधड़ी का कोई अवसर नहीं था। इस प्रकार, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अनुबंधों के एक हिस्से को सुधारने के लिए नीचे की अदालतों द्वारा जिस तरह से राहत दी गई है, वह पूरी तरह से अनुचित है और कानून में स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है। डिक्री के उस हिस्से को अनिवार्य रूप से अलग रखा जाना चाहिए। जो बचा है वह वचनबंधन का मामला है। यहां इस वादे को संबंधित मंत्री का बजटीय भाषण बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने दक्षिण कन्नड़ जिले में जनता को ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। सबसे पहले, कुछ वादी पक्ष द्वारा दायर रिट याचिकाओं में डिवीजन बेंच ने उन्हें खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि इन मामलों में प्रॉमिसरी एस्टोपेल का कोई सवाल ही नहीं उठता। उक्त निर्णय को चुनौती देने वाली अपील की विशेष अनुमति की याचिका को इस न्यायालय ने खारिज कर दिया और वादी पक्ष को सिविल न्यायालय में जाने की छूट दे दी। सवाल उठता है कि सिविल कोर्ट का दरवाजा किसलिए खटखटाया जाए? हमारे अनुसार, सिविल कोर्ट का रुख यह स्थापित करने पर हर्जाने के लिए मुकदमा करने के उद्देश्य से है कि विधानसभा में भाषण द्वारा उठाई गई उम्मीदों और राज्य द्वारा

निषेधाज्ञा लागू करने में राज्य की विफलता के कारण उन्हें नुकसान हुआ था। एक नीति। याचिका खारिज करते समय भी सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार सुरक्षित है। अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए, वादी को कुछ वादी द्वारा दायर रिट याचिकाओं में पहले से ही अस्वीकार किए गए वचन विबंध की याचिका के साथ सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है। न ही यह अदालत को डिवीजन बेंच में उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई बातों के पीछे जाने और प्रॉमिसरी एस्टोपेल के मामले को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, यह न्यायालय एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड में है। लिमिटेड एवं अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य। [1986] 1 एस.सी.सी. 133 में माना गया है कि रोक का सिद्धांत सरकारी नीति के स्तर पर लागू नहीं होता है। भारत संघ एवं अन्य में। बनाम गणेश राइस मिल्स एवं अन्य, जेटी (1998) 9 एससी 51, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना था कि किसी मंत्री द्वारा संसद में दिया गया भाषण नहीं दिया जा सकता है। वचन विबंधन के सिद्धांत को आकर्षित करने वाले किसी व्यक्ति से किया गया वादा या प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाता है। मेसर्स पाइन केमिकल्स लिमिटेड एवं अन्य में। वी.औसेनिंग अथॉरिटी और अन्य, [1992] 2 एस.सी.सी. 683, इस न्यायालय ने माना कि दस साल की अवधि के लिए बिक्री कर के भुगतान से

छूट जारी रखने के प्रस्ताव का जिक्र करने वाला वित्त मंत्री का बयान केवल एक बजट प्रस्ताव है जो पार्टियों को किसी भी अधिकार को जन्म नहीं दे सकता है और ऐसा हुआ है छूट की अवधि बढ़ाने वाले किसी निर्णय, आदेश या अधिसूचना के बराबर नहीं है, जो कि प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के आधार पर याचिका दायर करने के लिए आवश्यक थी। जिस तरह से उच्च न्यायालय सहित निचली अदालतों ने इन निर्णयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर काबू पाया, उसमें बहुत कुछ अपेक्षित नहीं है।

6. इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि राज्य में ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर मंत्री द्वारा विधानसभा में दिए गए भाषण के आधार पर वादी प्रतिज्ञा विबंधन के किसी भी मामले को खोजने के हकदार नहीं हैं।

17. इसके अलावा, यह देखा जाना चाहिए कि यह वादी का मामला नहीं है कि जनता को ताड़ी की बिक्री की अनुमति दी गई थी। उनका मामला यह है कि बाद में एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें सहकारी समितियों के माध्यम से ताड़ी की खरीद करने और इसे राज्य इकाइयों को आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया गया। ऐसा नहीं लगता कि सरकार अपने नीतिगत उद्देश्य से भी पीछे हट गयी हो। लेकिन वादी के मामले से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार

जनता को ताड़ी निकालने वालों द्वारा ताड़ी की बिक्री को रोकने के लिए बनाई गई नीति को पूरी तरह से लागू नहीं कर सकी। हमारे अनुसार, इससे अधिक से अधिक वादी को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह राज्य से क्षतिपूर्ति का दावा कर सके, यह स्थापित करने पर कि सरकार की ऐसी विफलता के कारण उन्हें क्षति हुई है।

18. यहां, हमें याद रखना चाहिए कि वादी सभी अनुभवी उत्पाद शुल्क ठेकेदार हैं जो खुली नीलामी में शराब बेचने के अधिकार के लिए बोली लगा रहे हैं। यह कुख्यात है कि ये नीलामियाँ अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हैं और मौजूदा ठेकेदार द्वारा अपने गढ़ को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। यह भी कुख्यात है कि इन नीलामियों में प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें बढ़ने की प्रवृत्ति दिखती है। राज्य ने बताया है कि विभिन्न अन्य केंद्रों के आंकड़ों में वृद्धि वर्ष 1989-90 की राशि से 300% अधिक है। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वादी द्वारा बोली उनकी गणना पर आधारित नहीं थी और एक दृष्टिकोण के साथ थी अपने- अपने क्षेत्रों में अमैक बेचने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिस्पर्धा को दूर करना

19. वादी जो चाहते थे वह एक व्यावसायिक उद्यम था

जिसमें जोखिम भी शामिल था। यदि उन्हें लगा कि जोखिम नहीं उठाया जा सकता है, तो यह उनका काम था कि वे अनुबंध को पूरी तरह से अस्वीकार कर दें। वास्तव में, जब सरकार ने स्पष्ट रूप से वादी की क्षतिपूर्ति में विफलता के कारण अनुबंधों को समाप्त करने का प्रयास किया जुलाई और अगस्त 1990 के महीनों के लिए सहमति के अनुसार किस्ट राशि वादी ने इस पर रोक लगाते हुए उच्च न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त किए समाप्ति और अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए वेंडिंग अरैक के साथ आगे बढ़े समझौतों के तहत. अनुबंध के निष्पादन पर जोर देकर और इसके तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के बाद, वादी इसे अस्वीकार करने के हकदार नहीं हैं अनुबंध के तहत उनके दायित्व। रोक, पारंपरिक या का कोई मामला नहीं वचन, यहाँ उत्पन्न होगा।

20. एस्टोपेल पर निष्कर्ष केवल संबंधित मंत्री द्वारा विधानसभा में अपने भाषण में किए गए वादे या दिए गए प्रस्ताव और सार्वजनिक रूप से ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध की नीति को लागू करने में सरकार की विफलता पर आधारित है। हमारा विचार है कि वादी द्वारा उठाई गई याचिका उनकी बोलियों के आधार पर उनके द्वारा किए गए दायित्व से मुक्त होने को उचित ठहराने वाली एस्टॉपेल की याचिका को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त

आधार नहीं रखती है और जैसा कि उनके द्वारा किए गए लिखित अनुबंधों में निहित है। सरकार। ऐसा कोई मामला नहीं है कि अनुबंध में कोई ऐसी शर्त शामिल है जो गलती है या इसमें कोई शर्त शामिल है जो राज्य पर कोई दायित्व डालती है, राज्य उस दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है।

21. इस स्थिति में, हमें नहीं लगता कि प्रॉमिसरी एस्टॉपेल, इसके दायरे और क्या हमारे सामने आने वाले मामले में, किसी को राहत देने की याचिका को बरकरार रखने से पहले नुकसान दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उन सभी निर्णयों पर चर्चा करना आवश्यक है। इसके दायित्व के अकेले पक्ष। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि इन मामलों में की गई प्रार्थनाओं को कायम रखने के लिए कोई आधार नहीं रखा गया है और समर्थन में कोई मामला स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए, हम इन मामलों में प्रॉमिसरी एस्टॉपेल और इसकी उपलब्धता के सवाल पर आगे चर्चा करने से बचते हैं। यह कहना पर्याप्त है कि यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ताओं को पार्टियों के बीच अनुबंध के संदर्भ में किस्ट राशि का दावा करने से रोक दिया गया है, पूरी तरह से अस्थिर पाया गया है।

22. ऊपर बताए गए कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं, निचली अदालतों के निर्णयों और डिक्री को रद्द करते हैं और

सभी लागतों के साथ दायर मुकदमों को खारिज करते हैं। इनमें से प्रत्येक अपील में उत्तरदाताओं द्वारा अपीलकर्ताओं को देय लागत रुपये निर्धारित की गई है। 50,000/-डी.जी

अपील की अनुमति.

नोटः- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सरफराज नवाज, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।